पीक आवर्स में बीएसईएस उपभोक्ताओं ने की बिजली खपत में 17,000 किलोवॉट की कमी

- *डिमांड रेस्पॉन्स प्रोजेक्ट* के तहत कम की कई बिजली की खपत
- उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 1 रूपये का इंसेंटिव भी मिला

नई दिल्ली: 17 अगस्त, 2017। बीएसईएस ने छह सप्ताह के लिए एक मैनुअल *डिमांड रेस्पॉन्स प्रोजेक्ट* शुरू किया था, जिसके तहत उपभोक्ताओं ने पीक आवर्स के दौरान अपनी बिजली खपत में 17,000 किलोवॉट की कमी की है। बिजली की अधिक खपत करने वाले 500 बड़े उपभोक्ताओं को इस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया था। इनमें से हर उपभोक्ता का बिजली लोड 500 किलोवॉट से अधिक था। प्रोजेक्ट में शामिल उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया था कि पीक आवर्स में जरूरत पड़ने पर, वे स्वेच्छा से अपना बिजली– लोड कम कर दें।

उपभोक्ताओं ने बिजली की खपत को नियंत्रित करने की इस मुहिम में बीएसईएस का पूरा सहयोग करते हुए छह सप्ताह के भीतर अपनी बिजली खपत में 17,000 किलोवॉट की कमी की। खास बात यह है कि प्रोजेक्ट में शामिल उपभोक्ताओं को बिजली की कम खपत करने के ऐवज में प्रति यूनिट 1 रूपये का वित्तीय इंसेंटिव भी दिया गया।

प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सलाहकार संस्था आईसीएफ और शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ मिलकर यह प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसके काफी उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए।

बीवाईपीएल के 500 बड़े उपभोक्ताओं के साथ शुरू किए गए इस पायलट प्रोजेक्ट को उनकी ओर से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। इसके उत्साहवर्धक परिणामों को देखते हुए इसे आने वाले दिनों में क्रमिक आधार पर पूर्वी, मध्य, दक्षिणी और पश्चिमी दिल्ली के अन्य इलाकों में भी लागू किया जाएगा।

उपभोक्ताओं को लाभ:

इस प्रोजेक्ट के तहत, उपभोक्ताओं से कहा गया था कि वे वॉशिंग मशीन, प्रेस जैसे अपने गैर–जरूरी बिजली उपकरणों को जरूरत पड़ने पर पीक आवर्स के दौरान स्वेच्छा से बंद कर दें। इस तरह के गैर–जरूरी उपकरणों को पीक आवर्स के बाद चलाने को कहा गया था, जिससे उपभोक्ता को कई खास दिक्कत नहीं हुई। साथ ही, उन्होंने पीक आवर्स के दौरान बिजली की खपत में जितनी यूनिट की कमी की, उतनी यूनिट पर प्रति यूनिट 1 रूपये की दर से उन्हें इंसेंटिव भी दिया गया। इसके अलावा, पीक आवर्स में बिजली की खपत में कमी आने से उपभोक्ताओं को और बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

डिस्कॉम्स को लाभ:

पीक आवर्स के दौरान बिजली की खपत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के कारण डिस्कॉम्स को शॉर्ट–टर्म आधार पर काफी मात्रा में अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़ती है। शॉट– टर्म आधार पर खरीदी गई लॉन्ग– टर्म आधार पर खरीदी गई बिजली के मुकाबले महंगी पड़ती है। डिमांड रेस्पॉन्स प्रोजेक्ट के व्यापक इस्तेमाल से बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम किया जा सकता है।

पर्यावरण को लाभ:

डिमांड रेस्पॉन्स प्रोजेक्ट को अगर बड़े स्तर पर लागू किया जाए, तो इससे पीक आवर्स के दौरान बिजली की खपत में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। इससे, बिजली बनाने में इस्तेमाल होने वाले कोयले की खपत में भी कमी आएगी, जिससे पर्यावरण बेहतर होगा। साथ ही, कोयला कम जलने के कारण सीओ2 के उत्सर्जन तथा ग्लोगल वॉर्मिंग में भी कमी आएगी।

बीएसईएस प्रवक्ता के मुताबिक, दुनिया के कई हिस्सों में डिमांड रेस्पॉन्स के माध्यम में पीक आवर्स में बिजली की खपत में 5 से 6 प्रतिशत तक की बचत होती है। जहां तक बीवाईपीएल की बात है, तो हम शुरूआत में पीक आवर्स में 2 से 5 प्रतिशत तक की बिजली बचत को लक्ष्य कर रहे हैं। वैसे, इस पहल के माध्यम से 30,000 से 75,000 किलोवॉट तक की बिजली की बचत हो सकती है।

डिमांड रेस्पॉन्स प्रोजेक्ट, दरअसल, डिमांड साइड मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके तहत उपभोक्ता, तय किए गए समय के दौरान स्वैच्छिक रूप से बिजली की खपत में कमी लाते हैं।

प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।